



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 वैशाख 1944 (श0)
(सं0 पटना 299) पटना, शुक्रवार, 20 मई 2022

सं० सं०-07 / विविध-28-56 / 2021-22-33(7) / स्था०
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प
11 मई 2022

विषय:-बिहार राज्य में अगले 5 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए कुल राशि 300 करोड़ (तीन सौ करोड़ रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की स्वीकृति।

लोक कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनों तक सुगमतापूर्वक एवं बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति में डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

2. डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम को बिहार राज्य में कार्यान्वित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रयोग के तौर पर पूर्व में डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम को राज्य के दो जिलों मुजफ्फरपुर एवं नालंदा में आंशिक रूप से लागू किया गया जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं।

3. राज्य मुख्यालय में एक अत्याधुनिक Command and Control Centre की स्थापना की गयी है, जो वर्तमान में कार्य कर रहा है। परन्तु मात्र दो जिलों में आंशिक रूप से डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के चलने के कारण इस Command and Control Centre से मात्र इन्हीं जगहों का आंशिक अनुश्रवण एवं नियंत्रण हो पा रहा है।

4. राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आमजनों तक सुलभ करने एवं Digital तकनीक के माध्यम से इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य में डिजिटल हेल्थ योजना प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस योजना के माध्यम से आम जनों को निम्नांकित सुविधा प्रदान किए जाने का उद्देश्य है :-

- बुनियादी चिकित्सीय जाँच एवं सामुदायिक स्वास्थ्य पहल का स्वचालीकरण (Automation) करना।
- राज्य की जनता के लिए 24x7 आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श प्राप्त करने की स्वचालित तकनीक के माध्यम से व्यवस्था करना।

(iii) राज्य की जनता के स्वास्थ्य का अनुश्रवण एवं उसमें सहयोग प्रदान करना।

(iv) मरीजों के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/उच्च चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों पर रेफर करने एवं उनके आवागमन की निर्बाध सुविधा प्रदान करने में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करना।

(v) मरीजों के चिकित्सीय जाँच एवं परामर्श को डिजिटल तकनीक के माध्यम से संधारित करना, ताकि किसी भी चिकित्सीय संस्थान में उन्हें जाँच रिपोर्ट का कागज ले जाने की आवश्यकता नहीं हो।

5. राज्य की जनता को उपर्युक्त लाभ प्रदान किए जाने के साथ ही इस योजना से राज्य के स्वास्थ्य सुविधा की प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी काफी सहायता मिलेगी। इस क्रम में इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित कार्य आसान हो जायेंगे :-

(i) पेशेवर चिकित्सीय व्यवस्था एवं सहायता की उपलब्धता एवं उनका अनुश्रवण आसानी से हो सकेगा।

(ii) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का एकरूप मानक तैयार करने में आसानी होगी।

(iii) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में संलग्न कर्मियों/संस्थानों/उपकरणों की कार्यक्षमता एवं कार्य प्रणाली का बेहतर प्रबंधन हो पायेगा तथा साथ ही साथ इसके परिणामों का भी बेहतर विश्लेषण हो पायेगा।

(iv) राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था का डिजिटल तकनीक के माध्यम से एकीकरण हो सकेगा।

(v) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं आम जनों के **Health Records** के ऑकड़े डिजिटल तकनीक के माध्यम से उपलब्ध रहने पर भविष्य के नीति निर्माण में इनका उपयोग हो सकेगा।

6. उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तथा नालंदा एवं मुजफ्फरपुर जिले में प्रयोगात्मक रूप से डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के उत्साहवर्धक परिणाम के फलस्वरूप बिहार राज्य में अगले 5 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए कुल राशि 300 करोड़ (तीन सौ करोड़ रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना में **Hospital Information Management System (HIMS)**, **Enterprises Resource Planning (ERP)**, **Community Service Management System(CSMS)**, **Electronic Health Record (EHR)**, **Citizen Web Portal**, **Integrated with Existing Applications**, **ABDM Roll Out** एवं **Command and Control Centre** का एकीकृत समावेश रहेगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत प्रस्तावित **Application** को एक **Secured Cloud Server** पर **Deploy** किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सभी सम्बन्धित कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना के पाँच साल पूर्ण होने के उपरांत इस योजना का संचालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस संदर्भ में आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

8. इस योजना के अन्तर्गत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, निम्न रूप में होगा :-

(i) भारत सरकार के द्वारा स्थापित मानकों (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) के अनुरूप होगा।

(ii) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी **key components** के साथ एक-दूसरे के अनुकूल (**Compatible**) होगा।

(iii) इस योजना में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ कोई दोहराव नहीं है अपितु यह दोनों एक दूसरे के अनुपूरक होंगे।

(iv) स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जितने भी आवश्यक **App** हैं उनको यथावत या **Upgrade** करके इसके साथ संबद्ध किया जाएगा।

(v) इस व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुपस्थिति विवरणी को वेतन भुगतान से संबंधित **App/Platform** के साथ संबद्ध किया जाएगा। साथ ही चिकित्सकों की अनुपस्थिति की समस्या के निराकरण में भी मदद मिलेगी।

9. इस योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है, जिसके तहत प्रथम वर्ष में इसके **Design Development** के साथ 3(तीन) जिलों में **Pilot Basis** पर **Go Live** किया जाएगा। इसके पश्चात् दूसरे वर्ष में इसे शेष 35 (पैंतीस) जिलों में **Roll Out** किया जाएगा।

10. इस योजना के Design Development में प्रथम वर्ष (2022-23) में रु0100 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) द्वितीय वर्ष (2023-24) में लगभग रुपये 80 (अस्सी) करोड़ तथा शेष तीन वर्षों (2024-25, 2025-26 एवं 2026-27) में Operation एवं Maintenance के लिए प्रति वर्ष 40 करोड़ की दर से कुल 120 (एक सौ बीस करोड़ रुपये) अर्थात् कुल 300 करोड़ रुपये (तीन सौ) की लागत अनुमानित है।

11. यह कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कराया जाएगा। इस कार्य हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर किया जाएगा तथा भुगतान हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को राशि आवंटित की जाएगी।

12. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20 मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-ऐलोपैथी-लघु शीर्ष-103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-उपशीर्ष-0103-स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार-सात निश्चय-2 विपत्र कोड-20-2210031030103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 28-04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद से किया जाएगा।

13. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

आदेश से,
राम ईश्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 299-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>